May 2022

UPMSRA eNews

Unity and Struggle

Organ of Uttar Pradesh Uttarakhand Medical and Sales Representatives' Association

UPMSRA Bhawan, B-S/42, Blunt Square, Lucknow – 226004 Email: upmsranews@gmail.com

Editor: Hemant Kumar Singh Email: upmsrastate@gmail.com

UPMSRA Fights for People's Health

जीवन रक्षक दवाओं का दाम 10% बढ़ाने का फैसला रद्द करो

UPMSRA Units campaigned on Medicine Related Issues on 17, 18 and 19/04/2022. Memorandum was sent to Prime Minister through email and through the District Magistrate. Leaflet was distributed in public. Special Meetings were organised to explain the Medicine Related Demands of FMRAI.

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) में शामिल 800 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाओं का दाम 10.7% बढ़ाने का आदेश दिया है. इससे एंटी-बायोटिक, एंटी-इंफ्लामेटरी, एंटी-सेप्टिक, गैस्ट्रो-इंटेस्टिनल, एंटी-फंगल, ओ आर एस, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, एच आई वी, किडनी रोग तथा अन्य बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी. वर्ष 2021 में 0.53%, वर्ष 2020 में 1.88%, वर्ष 2019 में 4.26% की मूल्य वृद्धि का आदेश NPPA ने दिया था.

भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को पूरी तरह से "मार्केट फोर्सेस" के हवाले कर दिया है. वर्ष 2022-23 का स्वास्थ्य बजट इसी दिशा में एक जन-विरोधी कदम है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का वर्ष 2021-22 का कुल बजट 88,655 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) था. वर्ष 2022-23 के लिये बजट 89,251 करोड़ रुपये है. अगर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित किया जाये तो स्वास्थ्य बजट में 7% की गिरावट आई है. वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य का संशोधित बजट सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का 0.382% था. वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य बजट घटकर, सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का 0.346% हो गया है. **हमारी यूनियन मांग करती है कि GDP का 5% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होना चाहिये. इस मांग के लिये 19/01/2022 को देश के सभी दवा प्रतिनिधियों ने देशव्यापी हड़ताल की थी.**

फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कर्मियों ने महामारी के दौरान कई मुश्किलों, वेतन में कटौती, भुगतान में देरी के साथ अक्सर जान गंवाने के बावजूद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा प्रदान करने के लिये सिर्फ 226 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है. वर्ष 2021-22 में यह 813 करोड़ रुपये था. क्या सरकार यह मान रही है कि देश भर में कोविड से संबंधित देखभाल के लिये प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है?

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) कोविड के दौरान गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में पूरी तरह विफल रही. तमाम विफलताओं के बावजूद, सरकार इस योजना के लिये बड़े और बेकार आबंटन जारी रखे हुये है. PMJAY का करीब 75% भुगतान निजी क्षेत्र को हुआ है. **PMJAY को बंद करके, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिये इन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए.**

बजट में सबसे बड़ा लाभ आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन को प्राप्त हुआ है. यह वास्तविक "स्वास्थ्य देखभाल" की उपेक्षा करते हुए "स्वास्थ्य कार्ड" पर अनुचित जोर देने के समान है. इस योजना से बड़ी आई टी कंपनियों और निजी बीमा कंपनियों को लाभ होगा जबकि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में 4106 करोड़ रुपये की कटौती की गई है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के लिए बजट 17% घटा दिया गया है. इससे कई स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों की फंडिंग प्रभावित होगी. कुल मिलाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में यह बजट पूरी तरह विफल है.

बहुआयामी विफलताओं को छुपाने के लिए बजट के आंकड़ों की प्रस्तुति को जानबूझकर अपारदर्शी और मुश्किल बना दिया गया है.

सार्वजनिक क्षेत्र में सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा देश की सबसे बड़ी जरूरत है. इनकी अनदेखी की वजह से, अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं, और भारत में चिकित्सा व्यय का 65% रोगियों द्वारा जेब से भुगतान किया जाता है. यह दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है.

Shahjahanpur

UPMSRA Memorandum to Prime Minister

वैक्सीन उत्पादक इकाइयों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों को पुनर्जीवित करें

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के लिये निम्न मांगों पर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया.

1) दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी शून्य करें. **2)** सकल घरेलू उत्पाद का 5% स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवंटित करें. **3)** बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय दवा कंपनियों के अधिग्रहण को रोकें. **4)** वैक्सीन उत्पादक इकाइयों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की दवा इकाइयों को पुनर्जीवित करें. **5)** विदेशों पर निर्भरता से बचने के लिए ऐक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) का उत्पादन सुनिश्चित करें. **6)** सभी दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगायें; सभी आवश्यक दवाओं की कीमतें कम से कम तय करें; लागत आधारित प्रणाली पर वापस लौटें; वर्तमान बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली को वैध बनाना बंद करें. **7)** पेटेंट कानून में कंपल्सरी लाईसेंस के प्रावधान के माध्यम से सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें. भारतीय पेटेंट कानून को कमजोर करने का प्रयास बंद हो. **8)** दवा क्षेत्र में कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दंड के प्रावधान के साथ विपणन का एक वैधानिक कोड तैयार करें. **9)** दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद करें. यह प्रथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के विपरीत है और इसके दुरुपयोग की आशंका है. ऑनलाइन फ़ार्मेसी के माध्यम से तर्कहीन और गैर-आवश्यक दवाओं के प्रचार की संभावना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ख़तरा है. **10)** 800 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाओं के दाम को 10.7% बढ़ाने के NPPA के फैसले को वापस लिया जाए.

Memorandum was sent to Prime Minister through email and through the District Magistrate. The campaign programme received good public response. UPMSRA shall continue public awareness programmes for pro-people health policies.

Basti

Etah

Mirzapur

Ghazipur

Balrampur

Varanasi

Ayodhya

Orai

Sultanpur

Mau

Sitapur

Saharanpur

Chitrakoot

Dehradun

Banda

Hardoi

Aligarh

UPMSRA Demands: Health for All Now

देश की जीडीपी का 5 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिये आबंटित करो

Lucknow

Pilibhit

Pratapgarh

Gorakhpur

Bareilly

Jaunpur

Allahabad

Lalitpur

Bulandshahr

Lakhimpur

Ambedkar Nagar

Ballia

Padrauna

Moradabad

Raebareli

Ghaziabad

Robertsganj

Bahraich

Etawah

Meerut

Bijnor

Farrukhabad

Gonda

Council Related Movement in UPMSRA

बग़ावत हर उस फ़र्द के ख़िलाफ़, जो हमसे मेहनत कराता है, मगर उसका दाम अदा नहीं करता

During COVID-19 pandemic pharmaceutical company owners are indulging in illegality by refusing to pay the wages to the sales promotion employees. Some pharma employers are shamelessly exploiting this pandemic to further bring miseries and dangers to the lives of fieldworkers and their families. Workers are being transferred, terminated and denied work; wages are deducted or not paid at all. The employers are violating the Sales Promotion Employees Act and other laws. The employers are bringing new work systems, and newer forms of reporting systems in total violation of laws. Employers are violating the legally binding bilateral settlements.

Councils and Council Sub Committees in UPMSRA are seriously implementing the Council Related Programmes to resist the unlawful acts of the employers.

ADL: Jaunpur IMA Secretary

ADL: Ghazipur

ADL: Gorakhpur

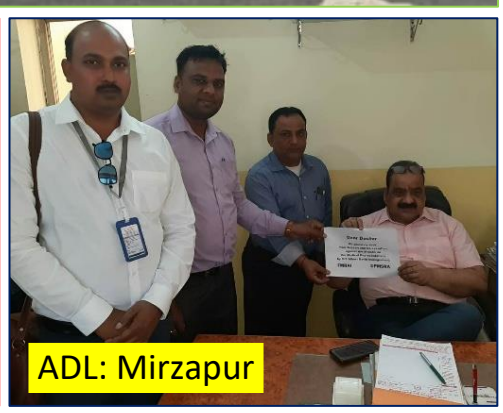
ADL: Mirzapur

ADL: Orai

ADL: Siddharthnagar

ADL: Haldwani

ADL: Maharajganj

ADL: Bulandshahr

ADL: Ballia

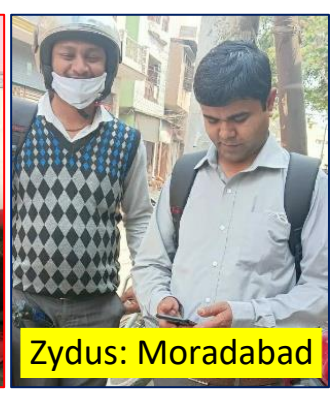
Zydus: Moradabad

ADL: Kashipur

Zydus: Deoria

Wallace: Ballia

ADL: Pratapgarh

Protest Programmes: Albert David, Alkem, AFD, Khandelwal, Zydus Healthcare, Indoco, RPG, Himalaya, JBCPL, Biological E, British Biologicals, Svizera, Wallace, Psychotropics, USV, Shreya, Glenmark, Bal Pharma.

Sanofi: All India Dharna at Head Office Mumbai by HAIRC on 10 & 11/05/2022

Wallace: All India Strike and Mumbai Office Dharna on 13, 14, 15/06/2022

Council Related Movement in UPMSRA

Council Movement has Declared Relentless War Against Wage-Slavery

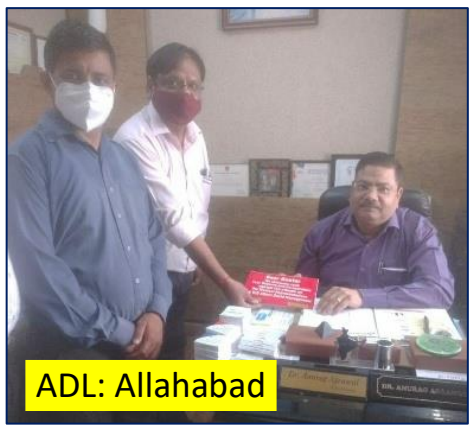

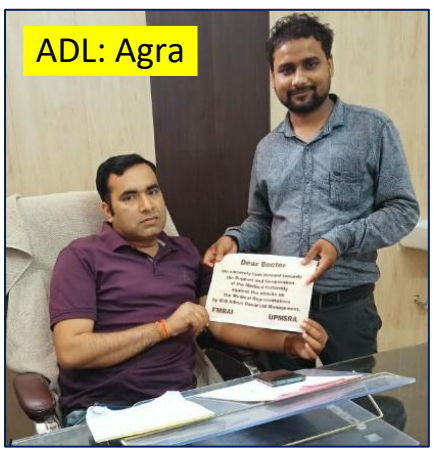

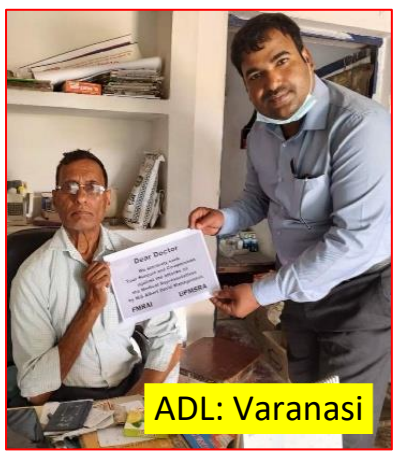

FMRAI Signs Wage Settlement in Three Companies

11th Wage Settlement in Stadmed

FMRAI and Stadmed management signed 11th successive Wage Settlement on 18/04/2022. The settlement is effective for a period of three years from 01/04/2020 to 31/03/2023. Basic Pay, FDA, VDA, HRA and non-Wage parts are revised upwardly. Minimum total benefit in second year is Rs. 4200 and maximum benefit is Rs. 11500.

The settlement has further strengthened the bilateral relations.

14th Settlement in Abbott (Solvay)

FMRAI and Abbott India (Solvay) management signed Wage Settlement on 13/04/2022. The settlement is effective for a period of three years from 01/01/2020 to 31/12/2022. All the heads including VDA are revised upwardly. Average benefit is Rs. 7500. Separately a Memorandum of Understanding was signed on usage of “iPad”.

The settlement has further strengthened the bilateral relations.

Settlement in Zydus (Vivo Division)

FMRAI and Zydus Healthcare Ltd management signed Wage Settlement and M.O.U. on 20/04/2022 for **Vivo Division**. The settlement is effective for a period of three years from 01/04/2018 to 31/03/2021.

Management has withdrawn their complaint and FMRAI has withdrawn review application. Both parties have agreed to discuss and settle the termination and transfer issues within three months and revert to the court.

47th Conference of East India Pharmaceutical Works Employees Union (EIPWEU) was held at Kolkata on 24/04/2022. Comrade Sanjay Narang (Moradabad H.Q.) was elected as Vice President and Comrade Ravi Sharma (Meerut H.Q.) was elected as EC Member of EIPWEU.

UPMSRA Units hold Annual General Body (AGB) Meetings

BANDA: UPMSRA Banda Unit AGB Meeting was held on 03/04/2022. Comrade Pratap Yadav and Sheshnath Tiwari attended as UPMSRA observer. **Banda Unit Membership for year 2022 is 152.** 90 members attended the AGB Meeting. 15 members Executive Committee was elected. Ashutosh Khare, Sanjay Kumar Bajpai and Anuj Tripathi were elected President, Secretary and Treasurer respectively.

BUDAUN: UPMSRA Budaun Unit AGB Meeting was held on 29/04/2022. Comrade Rameshwar Pandey attended as UPMSRA observer. **Unit Membership for year 2021 is 132.** 131 fieldworkers attended the AGB Meeting. 11 members Executive Committee was elected. Vyas Shankhdhar, Rupesh Singh and Sushant Singh were elected President, Secretary and Treasurer respectively.

LAKHIMPUR: UPMSRA Lakhimpur Unit AGB Meeting was held on 24/04/2022. Comrade Obijeet Talukdar attended the AGB Meeting as UPMSRA observer. **Lakhimpur Unit Membership for year 2022 is 232.** 70 fieldworkers attended the AGB Meeting. 15 members Executive Committee was elected. Sujeet Gupta, Adarsh Kumar Mishra and Pramod Kumar Singh were elected President, Secretary and Treasurer respectively.

Gonda Unit intervened in the issue of Ajay Kasaudhan (Lifecom Pharmaceuticals). **Ghazipur Unit** intervened in the issue of Sunil Kumar Rai (Mercury). **Meerut Unit** intervened in the issues of Aslam Saifi and Shekhar Kumar (both Shreya Lifesciences). All the issues were resolved.

UPMSRA Shahjahanpur Unit Purchases Plot for Unit Office

UPMSRA Shahjahanpur Unit purchased plot for construction of Unit Office. Plot registry was done on 13/04/2022. All the members of Shahjahanpur Unit have contributed for the Office. This Unit Office will help in strengthening UPMSRA Organisation and Movement in Shahjahanpur District.

FMRAI Purchases Office Building at New Delhi

FMRAI purchased Office building at New Delhi. The purchasing procedure was completed by registration on 27/04/2022. The Office address is Flat no. 2, First Floor, 4581/15, Daryaganj, New Delhi – 110002 (Near Happy School). FMRAI Secretariat Members visited the Office on 25/04/2022.

UPMSRA Foundation Day on 8th May

UPMSRA was formed on 8th May 1982 at Lucknow. It will complete 40 years on 08/05/2022. Please observe UPMSRA Foundation Day on 08/05/2022.

CITU Foundation Day on 30th May

CITU was formed on 30th May 1970 at Kolkata. It will complete 52 years on 30/05/2022. Please observe CITU Foundation Day on 30/05/2022.

Celebrate May Day and Uphold Working Class Unity and People's Unity

Campaign against Unemployment, Job Losses and Deteriorating Quality of Employment

May Day Lesson to Workers: Resist and Advance

Fight for Human Dignity, Livelihood, Justice, Liberty and Equality

एक मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस (International Labour Day) मनाया जाता है जिसे मई दिवस भी कहा जाता है. बहुत से देशों में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है लेकिन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्य भारत में ऐसा नहीं है. उन्नीसवी शताब्दी के नौवें दशक तक मजदूर अत्यंत अल्प और अनिश्चित मजदूरी पर सोलह-सोलह घंटे काम करने को मजबूर थे. The Communist Manifesto written by Karl Marx and Engels in 1848 had a great impact on workers across various countries that were feeling the heat of industrialisation. The great landmarks of the working class movement preceding internationalisation of May Day, apart from the Communist Manifesto of 1848, were the insurrection of Paris workers (1848), the founding of the First International under the guidance of Karl Marx and the rise of the Paris commune, the first state of the working class of 1871.

अमेरिका की National Labor Union ने अगस्त, 1866 में 8 घंटे के कार्य दिवस का फैसला लिया. **सितंबर, 1866 में जिनेवा कांग्रेस ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल (International Workingmen's Association) ने 8 घंटे के कार्य दिवस के कानून की मांग की और कहा कि कार्य दिवस की कानूनी सीमा एक प्रारंभिक शर्त है, जिसके बिना श्रमिक वर्ग के सुधार और मुक्ति के सारे प्रयास निष्प्रभावी साबित होंगे.** नारा था: आठ घंटे काम, आठ घंटे सामाजिक जीवन और आठ घंटे आराम. कार्ल मार्क्स ने 'दुनिया के मज़दूरों एक हो' का नारा दिया और कहा कि मज़दूरों के पास खोने को सिर्फ बेड़ियां हैं जबकि जीतने को सारी दुनिया है.

अक्टूबर 1884 में, Federation of Organized Trades and Labor Unions द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया कि 1 मई, 1886 से आठ घंटे का कार्य दिवस लागू किया जाएगा और मजदूर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे. इस मांग को लागू करवाने के लिये 1 मई 1886 को अमेरिका की सड़कों पर लाखों मजदूर उतर आए.

शिकागो (अमेरिका) उस समय एक मजबूत मजदूर आंदोलन का केंद्र था. शिकागो में सबसे बड़ी हड़ताल और प्रदर्शन हुआ. शिकागो में 4 मई 1886 को मजदूर आठ घंटे काम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान शिकागो की हेमार्केट (Haymarket) में पुलिस के जासूसों ने बम फेंका. प्रदर्शनकारियों से बदला लेने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई और सैकड़ों मज़दूर घायल हो गए. पुलिस उनके ऐसे बर्बर दमन पर उतर आयी कि शिकागो की धरती मज़दूरों के खून से लाल हो गई. तभी से उस संघर्ष की याद में हर साल एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है.

फर्जी मुकदमा चलाकर मजदूर नेताओं को साजिश का दोषी ठहराया गया. सात मजदूर नेताओं को मौत की सजा और एक को 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई. 11 नवंबर, 1887 को चार मजदूर नेताओं George Engel, Adolph Fischer, Albert Parsons और August Spies को सफेद लिबास में ढककर फांसी के तख्ते पर ले जाया गया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी गीत गाया और फांसी पर झूल गए. इसके एक दिन पहले 10 नवंबर 1887 को Luis Lingg ने जेल में आत्महत्या कर ली.

1889 में स्थापित सोशलिस्ट इंटरनेशनल (Second International) ने मई दिवस को एक अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी स्वरूप देने की पहल की. 1889 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हेमार्केट में मारे गये निर्दोष मजदूरों की याद में 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रुप में मनाया जायेगा और इस दिन सभी कामगारों का अवकाश रहेगा.

1 मई 1923 को मद्रास (चेन्नई) में कामरेड सिंगारवेलु चेट्टियार के नेतृत्व में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा भारत में पहला मई दिवस समारोह आयोजित किया गया था. इसी दिन भारत में पहली बार मजदूरों ने लाल झंडे का इस्तेमाल किया. एक सभा मरीना बीच पर और दूसरी सभा ट्रिप्लीकेन बीच पर आयोजित की गई थी. कामरेड सिंगारवेलु चेट्टियार ने सभा की अध्यक्षता की जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार मई दिवस को अवकाश घोषित करे. इस बात पर जोर दिया गया कि आजादी पाने के लिए दुनिया के मजदूरों को एकजुट होना होगा. **इस पहले मई दिवस समारोह की याद में, चेन्नई के मरीना बीच पर 1959 में Triumph of Labour (श्रम की विजय) मूर्ति स्थापित की गई.**

Since the Hay Market massacre, the world has witnessed tremendous successes for the working class movement. A class whose leaders were executed for demanding an 8-hour workday under capitalism, vanquished capitalism over one third of the world. The working class successes also gave a fatal blow to the old colonial system under which countries stood enchained by foreign rulers. Thanks to these achievements of the international working class movement, these countries are breathing the air of freedom. These victories were achieved at the cost of tremendous sacrifices on the part of the working class and its organisations.

May Days became focal points for the international revolutionary proletariat. To the original demand for the 8-hour day were added other slogans on which the workers were called upon to concentrate during their May Day Programmes. These included: International Working Class Solidarity; Universal Suffrage; War Against War; Against Colonial Oppression; Freeing of Political Prisoners; the Right to Political and Economic Organization of the Working Class.

The fact is that May Day which was originally to rally support for 8-hours' work, was now invested with the content of the general line of the revolutionary working class movement. Though the Chicago demonstration started on the question of 8-hour working day, the international tradition of May Day went far beyond demands. It combined the fight for partial demands, having revolutionary significance, with the call for ending the capitalist order and capture of political power by the working class and a call for international unity of the working class.

आज भी न संघर्षों का इतिहास बदला है, न श्रम, उत्पादन व पूंजी का मूल संबंध. आज जब मजदूरों को नए अत्याचारों व असुरक्षाओं के हवाले किया जा रहा है, मजदूर आंदोलनों की पहले से ज्यादा जरूरत है. मजदूर दिवस, श्रम को पूंजी की सत्ता से मुक्ति दिलाने, उसकी गरिमा को पुनर्स्थापित करने और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की चेतना जगाने का दिन है. मई दिवस, वह दिन है जो पूंजीपतियों के दिलों में डर पैदा करता है और मज़दूरों में बेहतर दुनिया की उम्मीद जगाता है.

Each contingent of the world working class must be in the forefront of the struggle in keeping the revolutionary traditions of May Day. In India the working class is yet to realise its responsibility and throw its full weight in the struggle against exploitation and attack on rights of the workers. CITU calls upon the entire working class, the toiling people and all sections of patriotic people oSf the country to participate in May Day Programmes and actively support and join the struggle against the disastrous decision of the central government to hand over public assets, the people's wealth to a handful of their corporate cronies. The fight to save the country from corporate greed shall intensify in the coming days.

The fieldworkers should intensify their struggles for humane working and service conditions and resist the attack on labour rights. May Day inspires us that despite grave difficulties, unity and struggle with working class ideology will create an exploitation free society with dignity of labour.